

न्यायालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: 1320

वाट संख्या: 1/821 71



दिनांक: 16.11.83

विषय: राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्जित हाउसिंग कॉलोनी निर्माण हेतु अधिप्राप्त के अधीन भूमि का आंशिक अवाडी ग्राम सुखालपुरा खसरा नम्बर 34 रकबा 3 बोधा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 5 बोधा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 40 रकबा 1 बोधा 10 बिस्वा ख.नं. 58 रकबा 4 बोधा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 4 बोधा खसरा नम्बर 163 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 20 बोधा 2 बिस्वा.

पोठासोन अधिकारी:--

श्री मूलचंद आर.ए.एस., विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर

पक्षकार:--

1. गोपाल पुत्र डूंगा माली, निवासी सुखालपुरा तहसील सांगानेर जरिये श्री रामचन्द्र शर्मा, एडवोकेट.
2. राजस्थान आवासनमण्डल, जयपुर जरिये श्री दीनदयाल शर्मा, एडवोकेट.

:: अवाडी ::

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

राजस्थान राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर को ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् हाउसिंग कॉलोनी बनाने हेतु निम्न ग्रामों के सामने अंकित भूमि को अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अधिप्राप्ति अधिनियम 53 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जावेगा को धारा 4 के अन्तर्गत दिये जिसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-71721 न.वि.आ./11/81 दिनांक 12.1.1982 को राजस्थान राजपत्र के भाग 'ख' में दिनांक 13.1.82 को प्रकाशित भूमि का हस्तांतरण किया गया।

121

को गई । ग्रामनाम भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:---

क्रम संख्या	नाम भूमि	बीघा	बिस्वा	म.
1.	सुखालपुरा	807	06	
2.	देवरी	679	04	
3.	झालाना चौड	936	03	
4.	बलरामपुरा उर्फ खेडावाला	38	11	
5.	मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावात	27	07	
6.	नन्दकिरीरपुरा उर्फ मान्यावात	82	04	
योग:		2570	15	

121 तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति को अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उप धारा 111 में उल्लेखित नोटिस में प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति क्रमांक स्फ-71721 नं. वि.आ./11/81 दिनांक 9 फरवरी 1982 जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 9.2.82 भाग "ख" में प्रकाशित हुई के द्वारा अधिकृत किया ।

विभागाधिकारी
राज्य एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

131

धारा 17141 की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् अवाप्ति के अन्तर्गत भूमि का सर्वे तहसीलदार सांगानेर से कराया गया । तत्पश्चात् समस्त खाते दारो/हितधारियों के नाम भूमि का कब्जा स्थानान्तरण हेतु तथा अपना हक व हित प्रस्तुत करने हेतु पब्लिक नोटिस नियमानुसार दिनांक 5.5.82 को प्रकाशित कराया गया। पब्लिक नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिवस पश्चात् निम्न लिखित तिथियों में भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया।

दिनांक 22.5.82

ग्राम सुखालपुरा, नन्द किशोरपुरा
उर्फ मान्यावास एवं देवरी

दिनांक 24.5.82

झालाना चांड, बलरामपुरा उर्फ
खेडावाला, मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावासभूमि का कब्जा जिस को कर माके पर ही राजस्थान
आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सभलाया गया।

141

उपरोक्त कार्यवाही के अन्तर्गत विभिन्न खातेदारों/
हितधारियों को अधिनियम की धारा 9131 के अन्तर्गत
नोटिस जारी किये गये समस्त खसरा नम्बर की भूमि का
वैलम प्रस्तुत करने हेतु सूचना दैनिक पत्र राजस्थान पत्रिका
में दिनांक 19.6.1982 में भी प्रकाशित हो गई।

151

अधिनियम की धारा 9111 के पब्लिक नोटिस प्रकाशित
करने से पूर्व सरकार के पत्र क्रमांक एफ-71721 न.वि.आ.
11/81 दिनांक 29.4.1982 द्वारा ग्राम सुखालपुरा, झालाना
चांड एवं गोल्यावास की कुछ खसरा नम्बरों की भूमि को
अव्याप्त कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित को गई, अतः
अधिनियम की धारा 9111 के नोटिस में स्थान आदेश संबंधित
भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया एवं कब्जा भी नहीं लिया
गया। इस प्रकार स्थान आदेश संबंधित भूमि को छोड़ते हुए
तथा राजस्व अधिकार में अंकित रकबे से अधिक रकबे को छोड़ते हुए
निम्न ग्रामों के आगे अंकित भूमि का कब्जा दिनांक 22.5.82 एवं
24.5.82 को लिया जाकर राजस्थान आवासन मण्डल को सौंपा गया:

नाम ग्राम	बोधा	बिस्वा
1. बलरामपुरा उर्फ खेडावाला तहसील सांगानेर	38	11
2. मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर	24	06
नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर	82	04
झालाना चांड तहसील सांगानेर	852	10
देवरी तहसील सांगानेर	667	13
6. सुखालपुरा तहसील सांगानेर	726	19

योग:

आधिकारी

आवासन विभाग
जयपुर.

खसरा नम्बर 34 रकबा 3 बोधा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 5 बोधा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 1 बोधा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 रकबा 4 बोधा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 रकबा 4 बोधा, खसरा नम्बर 163 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 20 बोधा 2 बिस्वा है। इसमें से खसरा नम्बर 163 रकबा 17 बिस्वा श्री गोपाल पुत्र इंगा के खातेदारों की भूमि नहीं है पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि खसरा नम्बर 163 रकबा 17 बिस्वा का कब्जा फर्द पृष्ठ संख्या 5 के अनुसार श्री रामल्या पुत्र स्थनाथ जाति जाट के नाम से बना हुआ है तथा कब्जा भी श्री रामल्या से ही लिया गया है तथा वाद संख्या 1/82/24 के अनुसार श्री रामल्या ने खसरा नम्बर 163 रकबा 17 बिस्वा का क्लेम प्रस्तुत किया है अतः खसरा नम्बर 163 रकबा 17 बिस्वा का निर्णय वाद संख्या 1/82/24 में किया जायेगा।

खसरा नम्बर 58 रकबा 4 बोधा 5 बिस्वा का क्लेम मूल रूप से श्री पेमा, मोती पि. गोपाल ने किया है उक्त खसरा नम्बर का राजस्व रेकार्ड के अनुसार खातेदार कृष्ण भी श्री पेमा, मोती पि. गोपाल ही है किन्तु दिनांक 21.8.82 को जरिये प्रार्थना -पत्र श्री प्रदीप चौधरी ने उक्त खसरा नम्बर 58 रकबा 4 बोधा 5 बिस्वा को अपनी खातेदारों की भूमि बतलाते हुए मुआवजे को मांग को है इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 58 रकबा 4 बोधा 5 बिस्वा के दो दावेदार मेरे सामने उभर कर आये है अतः मैं श्री पेमा, मोती पि. गोपाल की ~~उक्त~~ भूमि खसरा नम्बर 34, रकबा 3 बोधा 15 बि. खसरा नम्बर 39 रकबा 5 बोधा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 1 बोधा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 154 रकबा 4 बोधा कुल रकबा 15 बोधा जिसका कि आंशिक अवार्ड दिया जा रहा है ये ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर की 726 बोधा 19 बिस्वा भूमि में सम्मिलित है जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है एवं खसरानं. 58 रकबा 4 बोधा 5 बिस्वा भूमि को छोड़ कर अवार्ड दिया जा रहा है।

नोटाधिकारी विभाग
अस एवं अवास्त विभाग
स्थान, जयपुर.

क्र.सं.	नाम दावेदार/ हितधारी	खसरा	रकबा बोधा- बिस्वा	किस्म भूमि
1.	प्रेमा, मोती पितरान	34	3-15	चाही
	गोपाल जाति माली	39	5-15	,,
	सुखालपुरा तह. सांगानेर	40	1-10	बारानो-1
		154	4-00	चाही
				...5...

पञ्चावली के अवलोकन पर पाया कि श्री गोपाल पुत्र
झूठा माली का विरासत का नामान्तरकरण श्री **प्रेम. मोती**
मोती मिश्राम गोपाल माली के हक में नामान्तरकरण संख्या
51 दिनांक 10.9.80 को स्वीकारही चुका है, अतः इनको
खातेदार काश्तकार माना जाता है।

171

उपरोक्त खेती नम्बर के दावेदाराने अपना अपना हक
व हित बतलाते हुए अधिनियम की धारा 9131 के संदर्भ में
जो क्लेम प्रस्तुत किये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है:---

1. प्रेम पुत्र गोपाल माली के हिस्से का प्रस्तुत क्लेम:--

क. भूमि रकबा 19 बोधा 5 बिस्वा	
की 45,000/- रुपये प्रति बोधा की	
दर से कीमत 8,66,250/- का 1/2 भाग	4,33,125.00
ख. भूमि 19 बोधा 5 बिस्वा की	
पाटेन्सियल वल्यू 15,000/- प्रति बोधा	
की दर से रु. 2,88,750/- का 1/2 भाग	1,44,375.00
ग. भूमि विकास व्यय 40,000/-का 1/2 भाग	20,000.00
ध. मिट्टी को डोलो की कीमत	3,807.00
ड. आवासीय पुख्ता मकान की कीमत	67,120.00
च. आबादी की भूमि 468 वर्गज की 50/-	
रुपये प्रति वर्गज से कीमत	23,400.00
झ. छप्पर धर आदि की कीमत	7,453.00
झ. सीमेन्ट के नल व होंदियों की कीमत	1,827.00
झ. वृक्षों का मुआवजा	8,600.00
ट. फलों से आय का मुआवजा	10,000.00
ठ. फिफ्टींग व रिमूवल चार्जेज	2,000.00
ड. अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा, मुआवजे	
की राशि 10 प्रतिशत	72,270.00
ड. अवाप्ति को कार्यवाही में धना व्यय का	
5 प्रतिशत मुआवजा	36,135.00
त. दिनांक 22.5.82 से मुआवजा मिलने तक	
6 प्रतिशत ब्याज	

2. श्री मोती पुत्र गोपाल माली के हिस्से का प्रस्तुत क्लेम

क. भूमि रकबा 19 बोधा 5 बिस्वा	
की 45,000/- रुपये प्रति बोधा की	
दर से कीमत 8,66,250/- का 1/2 भाग	4,33,125.00
ख. भूमि 19 बोधा 5 बिस्वा की	
पाटेन्सियल वल्यू 15,000/-प्रति बोधा	
की दर से कीमत, 8,66,250/-का 1/2 भाग	1,44,375.00
ग. भूमि विकास व्यय 40,000/-का 1/2 भाग	20,000.00

1. मिट्टी की डोला की कीमत	4,077.00
2. आवासीय प्लॉट मकान की कीमत	89,807.00
3. छप्पर घर व छप्पर की कीमत	6,120.00
4. सीमेंट के भूमिगत नल की कीमत	46.00
5. पेड़ों का मुआवजा	29,000.00
6. कुओं से आय का मुआवजा	10,000.00
7. शिक्षा व रिमायन चार्ज	2,000.00
8. अनिवार्य आपाती का मुआवजा 10 प्रतिशत	72,855.00
9. आपाती कार्यवाही में धन व्यय का मुआवजा 5 प्रतिशत	36,428.00
10. मुआवजे की राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज	

181

राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारान के क्लेम का उत्तर प्रस्तुत कर भूमि की कीमत अधिक से अधिक रु 10,000/- प्रति बोधा, अर्धेन डोला 1,656.50 कुआ 14,000/- दूसरे का 13,500/- छप्परराज के 1526/- मकानात का 71247.75 एवं दूसरे मकान 46,763.73 होदीज के 212.50 धुमटी 125/- वाटर टैंक 465.50 एवं अन्य वाटर टैंक के 50/- देना जायज प्रस्तावित किया है।

191

आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता ने श्री पेमा, मोती पिसरान गोपाल जयवर्ति माली के भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स का तखमोना निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है :-

111 मिट्टी का डोला	2,313.00
121 कुआ	28,000.00
131 कुआ	27,000.00
141 छप्परस हट	30,412.00
151 आवासीय मकान	1,42,495.50
161 आवासीय मकान	73,527.55
171 होदीज	425.00
181 धुमटी	931.00
191 धुमटी	
110 वाटर टैंक	252.00
111 वाटर टैंक	100.00

1101

दावेदारान को आर से अपने क्लेम के समर्थन में निम्न लिखित दस्तावेजात प्रस्तुत किये है:-

111 नकल विक्रय पत्र दिनांक 1.1.73

- 121 नकल विक्रय पत्र दिनांक 19.7.82
- 131 नकल विक्रय पत्र दिनांक 9.8.71
- 141 नकल विक्रय पत्र दिनांक 15.11.73
- 151 खसरा नम्बर सम्मत 2034 से 2038
- 161 जमवाबंदी सम्मत 2025 से 2028
- 171 नकल पददा आबादी भूमि दिनांक 16.3.82.
- 181 नकल खसरा गिरदावरी सम्मत 2020 से 2029

1111 आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का ब्यारा निम्न प्रकार से है :--

- 111 नकल विक्रय पत्र दिनांक 4.1.1982
- 121 नकल विक्रय पत्र दिनांक 15.4.1981
- 131 तखमीना द्वारा आवासीय अभ्यन्ता.

1121 मेने इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि का मौका निरोक्षण इस योजना से सम्बन्धित आवासीय अभ्यन्ता एवं पक्षकारान के अभिभाषकण के साथ किया पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकण की बहस सुनी । दावेदारान ने अपने क्लेम में 45,000/- प्रति बोधा को दर से मुआवजे को मांग को है तथा इसके समर्थन में विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है किन्तु पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों से उनके द्वारा मांगी गई भूमि को दर सिध्द नहीं होती है । तथा मैं दावेदारान द्वारा मांगी गई भूमि को दर को बहुत अत्याधिक मानता हूँ । आवासन मण्डल को ओर से दावेदारान के क्लेम के उत्तर में जवाब प्रस्तुत कर भूमि को दर 10,000/- प्रति बोधा देना प्रस्तावित किया है तथा इसके समर्थन में जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है उनसे भूमि की औसत कोमत 6,500/- प्रति बोधा आती है मैं इस भूमि को दर को भूमि को बढ़ती हुई कोमत व इसको पोटेन्शियलिटी को देखी हुए कम मानता हूँ । इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भूमि अपाप्ति को विज्ञप्ति दिनांक को भूमि को दर निर्धारित करना है क्योंकि इन मामलों में सम्बन्धित विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा 12.1.1982 को जारी की जा चुकी है । और इसके पश्चात इसी क्षेत्र के कई मामलों का निर्धारण भी किया जा चुका है जिसमें कृषि भूमि दर चाही 20,000/- प्रति बोधा, बारानी व बंजड 19,000/- प्रति बोधा

आवासीय अधिकारी
आवासन विभाग
अजमेर.

एवं सड़क की सीमा को आने वाली भूमि की दर 1,000/- अतिरिक्त प्रति बोधा निर्धारित की गई है। अतः इन दरों को मध्य नजर रखना न्यायोचित होगा। प्रस्तुत प्रकरण में बटल के दारान विद्वान अधिवक्ता दावेदारान ने तर्क प्रस्तुत किया कि दावेदारान की भूमि राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 40 रक्बा। बोधा 10 बिस्वा को छोड़ कर बाकी दर्ज है किन्तु वास्तव में इस प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण भूमि बाही के सम में काम में ली जा रही है। अपने इस तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान खसरा गिरदावरी सम्मत 2034 से 2038 की ओर आकर्षित किया और कहा कि खसरा नम्बर 40 में गेहूँ, मटर, आदि की फसल होना आंकित है। इसके अलावा इस भूमि की सिंचाई कुए से की जाती है अतः इस भूमि को बाही माना जाना कानूनन न्यायोचित है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि भूमि सड़क से बिल्कुल समीप सम्बन्धित है, अतः इन तथ्यों को मध्य नजर रख कर भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाना चाहिए। मांका निरीक्षण पर मेने पाया कि भूमि सिंचित है, उपजाऊ है तथा सड़क सीमा में है अतः मैं भूमि का मुआवजा 21,000/- प्रति बोधा का दर से देना न्यायोचित मानता हूँ। विद्वान अधिवक्ता ने श्री पेमा, पुत्र गोपाल माली की आबादी की भूमि 468 वर्गगज की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर कहा कि श्री पेमा के पास एक 468 वर्गगज का आबादी का आबादी भूमि में भू खण्ड है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत कल्याणपुरा पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर का पत्रावली में प्रस्तुत किया हुआ है। इस भू खण्ड का मुआवजा 50/- प्रति वर्गगज के हिसाब से दिलाया जाना चाहिए। क्योंकि ये शरिया आबादी के हिसाब बहुत ही मोठे का है मेने दावेदारा-न द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत उपरोक्त आबादी के भू खण्ड के पट्टा नं. 28 का अवलोकन किया। मैं इस आबादी के भू खण्ड का मुआवजा 20/- रुपये प्रति वर्गगज से कम देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। विद्वान अधिवक्ता ने श्री पेमा के हिस्से में भूमि के चारों तरफ लगी मिट्टी के डोले की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कर मांग की कि डोला लगभग पांचफिट उचा, तथा बहुत मोठा लगा हुआ है अतः इसका मुआवजा हमारे क्लेम के अनुसार दिया जाना

विशेषाधिकारी
विकास एवं श्रम विभाग
जयपुर.



चाहिए। श्री पेमा ने हिस्से की भूमि में कुल 32 पेड स्थित हैं पेड बहुत बड़े-बड़े हैं जो कि पेडों की मोटी हैं एवं उनकी विशालता को देखते हुए मुआवजा तय किया जाना चाहिए। श्री पेमा ने अपने हिस्से की भूमि में पानी की सप्लाई के लिए भूमि के अन्दर सीमेन्ट के नल लगा रखे हैं तथा सीमेन्ट की होदिया बना रखी है अतः इनका मुआवजा भी दिलाया जाना चाहिए। विद्वान अधिकता ने मेरा ध्यान श्री पेमा के आवासीय मकान की ओर दिलाया और कहा कि मकान बहुत लम्बा चौड़ा बना हुआ है, इसमें कई कमरे हैं मकान का बनावट पक्का है, इस मकान में पत्थर के बड़े बड़े खम्बे लगे हुए हैं इसके अलावा श्री पेमा के छप्पर हट्ट बने हुए हैं जिनमें 12-12 फुट लम्बी कई पट्टीया लगी हुई हैं तथा मोटी- मोटी एवं काफी लम्बी लम्बी लकड़ियों के धूनी और बलसोण्डे लगे हुए हैं, इन सब का मुआवजा इनमें लगे सामान, इनकी बनावट, इनकी लम्बाई, चौड़ाई आदि को मध्य नजर रख कर तय किया जाना चाहिए। विद्वान अधिकता ने मेरा ध्यान श्री मोती के बने मकान की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि श्री मोती का मकान भी काफी लम्बा चौड़ा है खिड़की, दरवाजे लगे हुए हैं मकान की किर्निशें बढिया हैं अतः इसका मुआवजा भी मोती के मकान की बनावट आदि को मध्य नजर रख कर दिया जाना चाहिए। मोती हिस्से में आई भूमि में मोती के 39 वृक्ष मौजूद हैं तथा मोती के भी छप्पर हट्ट बने हुए हैं उनमें भी पट्टीया लगी हुई हैं तथा उस घर बंधा हुआ छप्पर बहुत मोटा और मजबूत है अतः इसका मुआवजा भी दिलाया जाना चाहिए। मैं इस प्रकरण की भूमि का मोका निरीक्षण करते वक्त पेमा मोती की भूमि पर कुल 71 वृक्ष खड़े पाये। मैं वृक्षों का मुआवजा 7,100/- से कम देना न्यायोचित नहीं समझता। इस जोत पर पेमा मोती के सीमेन्ट के नल व होदिया स्थित हैं उनका मुआवजा 1500/- रुपये देना न्यायोचित है। पेमा मोती की भूमि के चारों ओर डोली लगी हुई हैं डोलों का मुआवजा मैं आवासन मण्डल के तखमीने के अनुसार 2313/- तथा

सहायिका
विभाग
अनुर.

श्री पेमा मोती के आवासीय मकान उनके छप्पर हटस आदि को बनावट, मकानों की फर्निचर एवं उनकी बनावट आदि को देखी हुए मुआवजे के रूप में आवासीय अभियन्ता के तहसीने के अनुसार छप्पर हटस के 30, 412.20 तथा आवासीय मकानों के 1, 42, 495.50 एवं दूसरे आवासीय मकान के 73, 527.55 देना न्यायोचित मानता हूँ।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अर्जेंन्सा मानते हुए अधिनियम का धारा 17(4) में अवाप्त की गई है। अतः अधिनियम का धारा 23(2) के अनुसार सोलेशियम 10 प्रतिशत मुआवजे का राशि पर लदाया जावे। इस तर्क के संबंध में मेने अधिनियम की धारा 23(2) का अध्ययन किया मैं विद्वान अधिवक्ता के तर्क से सहमत हूँ तथा 10 प्रतिशत सोलेशियम मुआवजे की राशि पर दिया जाना न्यायोचित मानता हूँ। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अधिनियम की धारा 34 के अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाना आवश्यक बतलाया है क्योंकि जोत का कब्जा दिनांक 22.5.82 122 मई, 1982 को 6, 77, 045 आवासन मण्डल को सँभलाया जा चुका है मैंने अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन किया अतः मैं इस तर्क से भी सहमत हूँ।

113

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में

मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :---

श्री पेमा, श्रीमोती पिसरान गोपाल माली को मिलने वाला मुआवजा:

1. भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 3 बीधा	
15 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा	
5 बीधा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 49	
रकबा 1 बीधा 10, खसरा नम्बर 154	
रकबा 4 बीधा कुल रकबा 15 बीधा	
21,000/- प्रति बीधा की दर से	
मुआवजा	3, 15, 000.00
2. आबादी की भूमि 468 वर्गज का	
का मुआवजा 20/-प्रति वर्गज की	
दर से	9, 360.00

योग: 3, 24, 360.00

विभाग

ग। आवासीय मकान का मुआवजा	3, 24, 360.00
घ। आवासीय मकान का मुआवजा	1, 42, 495.50
ङ। छप्पर हटान का मुआवजा	73, 527.55
च। वृक्षों का मुआवजा	30, 412.20
ज। सीमेंट के नेल एवं होटिया का मुआवजा	7, 100.00
झ। सिंहरों को डोली का मुआवजा	1, 500.00
	2, 313.00

योग: 5, 81, 708.25

झ। अनिवार्य अवकाश का मुआवजा
10 प्रतिशत को दर से

58, 170.82

योग: 6, 39, 879.07

ट। मुआवजे को राशि पर 4 प्रतिशत
को वार्षिक दर से साधारण ब्याज
22.5.82 से 14.11.83 तक

37, 966.15

कुल योग: 6, 77, 845.22

इस प्रकार आज दिनांक 14.11.1983 को कुल रुपये 6, 77, 845.22 अक्षरे छः लाख सत्तर हजार आठ सौ पैंताली रुपये 22 पैसे मात्र का अवार्ड घोषित किया गया। अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड शामिल पत्रावली हो। एवं अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार सम्बन्धित खाते-द्वारा को सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर, सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर एवं तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन
विभाग, राज० जयपुर.

क्रमांक: 1320-23

दिनांक: 16.11.83

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज० जयपुर
2. श्रीमान सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर
4. श्री वेमा, श्री मोती पि. गोपाल मालो निवासी सुखालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर.

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

01C